DEMONSTRATION AGAINST SETTING UP A SLAUGHTER HOUSE IN HARYANA

6580. SHRI ARJAN SINGH BHADORIA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 630 on the 14th March, 1968 and state;

(a) whether the report from the Government of Haryana has been received in connection with the agitation at Kundli village;

(b) if so, the details thereof and whether a copy of the same will be laid on the Table; and

(c) whether it has been decided to shift the factory from this village?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of draft reply giving the required details, sent by the State Government of Haryana to the Starred Question No. 630 asked on 14th March, 1968 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. L.T.-1965/68.*]

(c) Establishment of meat processing factories is a State subject and therefore the matter rests with the State Government of Haryana.

FOOD POLICY

6581. DR. RANEN SEN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government intend to introduce any changes in the present food policy in view of the bumper crop this year and the consequent improvement in the stock position; and

(b) if so, the changes proposed to be introduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The food policy is evolved in consultation with the Chief Ministers of States at the beginning of each crop season. While formulating the policy for the current rabi crop emphasis was laid on maximising internal procurement with a view to build an adequate buffer stock by utilising the opportunity created by the bumper rabi crop.

(b) Changes in the present policy will be decided after the Chief Ministers' Conference to be held before the ensuing kharif season, when a clearer picture of the crop prospects is available.

कृषि उद्योग निगम

6581-क. **श्री महाराज सिंह भारती**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में कृषि-उद्योग निगम स्थापित किये गये हैं तथा निगम द्वारा स्थापित किये गये उत्पादन एककों की संख्या कितनी है तथा उनका स्वरूप क्या है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां निगम ट्रैक्टर विद्युत-चलित हल और अन्य कृषि उपकर के निर्माण के लिये कारखाने स्थापित कर रहा है ; और

(ग) कब उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) कृषि-उद्योग निगम 12 राज्यों में स्थापित किये जा चुके हैं अर्थात् आन्ध्र, असम, बिहार, हरियाणा, केरल,

मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कुछ निगमों द्वारा स्थापित उत्पादन–एककों की संख्या तथा उनके स्वरूप का विवरण नीचे दिया गया है :—

(1) निगम ने पशु एवं मुर्गी चारे–दाने के उत्पादन के कामों को आरम्भ कर दिया है।

महाराष्ट्र

निगम ने अधोलिखित कारखानों, प्लान्टों की स्थापना का कार्य शुरू किया है।

(1) कैटल फीड कम्पाउन्डिंग फैक्टरी, आरे

(2) पोल्ट्री फीड कम्पाउन्डिंग. फैक्टरी, चिन्चवाद

(3) सुपर फोस्फेट प्लान्ट, रासायानी

(4) दो एन. पी. के. ग्रेनुलर फर्टि–लाइजर प्लासन्ज्ज, डोविटल्ड विद सुपर–फोस्फेट प्लान्ट, रासा-यानी

(5) मक्का पीसने वाला प्लान्ट, पिम्परी।

पंजाब

निगम ने फिल्लौर के पास बीज के गुणन के लिये कार्यक्रम शुरू किया है।

उत्तर प्रदेश

इसने कृषीय औजारों के उत्पादन और आयातित फैक्टरों का एकत्रण करने के लिये लखनऊ में ताल कटोरा वर्कशाप को हाथ में ले लिया है। एकत्रण कार्यक्रम को चालू करने के लिये, निगम के 1000 जैकट–2011 ट्रैक्टरों का नितन कर दिया गया है जो एस के डी अवस्था में आयात किये जा रहे हैं। इसने डालिगंज में फ्रूट प्रोसैसिंग एन्ड प्रीजर्विंग फैक्टरी को भी हाथ में ले लिया है।

(ख) एवं (ग): इन में से कोई सा भी निगम अभी ट्रैक्टर और शकि–हल के निर्माण करने का कार्यक्रम नही रखता है। तथापि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि–उद्योग निगम के पास आयातित ट्रैक्टरों के एकत्रण के लिये कार्यक्रम है। 200 जकटर–2011 ट्रैक्टरों के प्रथम बैच के एकत्रण किये जाने की शीघ्र ही आशा है। निगम ने कृषीय औजारों का उत्पादन करना भी आरम्भ कर दिया है। हरियाणा निगम के पास आयातित ट्रैक्टरों के एकत्रण करने एंव कृषीय औजारों के निर्माण करने के लिये एक कार्यक्रम विचाराधीन है।

राष्ट्रीय वेतन आयोग

6581–**ख. श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को यह सुझाव दिया है कि एक राष्ट्रीय वेतन आयोग नियुक्त करना देश के लिये हितकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). लौह तथा इस्पात उद्योग सम्बधी अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया है कि कृषि, असंगठित क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय मजूरी आयोग बनाना वांछनीय होगा। अध्ययन दल की रिपोर्ट राष्ट्रीय श्रम आयोग को और न कि सरकार को पेश हुई है। सरकार इस